International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 11, November 2022
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

ग्रामीण भारत में शहरी विकास के रुझान और स्वरूपकाअध्ययन

SHOURYA PRATAP SINGH

Research Scholar, Sunrise University, Alwar Rajasthan

DR. OM PRAKASH SHARMA

Research Supervisor,Sunrise University, Alwar Rajasthan

सारांश

भारत में शहरी प्रणाली एक लंबे और जटिल इतिहास का परिणाम है और शहरीग्रामीण द्वंद्ववाद को चिह्नित करता है। जबकि शहरी भारत को अक्सर आधुनिक और श्वाणिज्यिकश् के रूप में देखा जाता हैए ग्रामीण भारत को आमतौर पर अदूरदर्शीए पिछड़ा और पारंपरिक माना जाता है। पारंपरिक रूप से कृषि क्षेत्रों में एक आधुनिक वाणिज्यिक क्षेत्र का प्रसार छोटे आकार के शहरों की कमी के कारण धीमी गति से होते हुए देखा गयाए और कई प्रमुख शहरों को अंतर्मुखी आर्थिक प्रणालियों के केंद्र के रूप में देखा गया है। भारत में सबसे अधिक चर्चित विषय है कि ग्रामीणशहरी विभाजन को कम कैसे किया जाएं और देश की दो अर्थव्यवस्थाएँ ग्रामीण और शहरी लगातार एक दूसरे से पृथक होती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में एक लोकप्रिय अवधारणा यह है कि शहरीकरण विकास को न केवल शहरी भारत की ओर तिरछा कर रहा हैए बल्कि ग्रामीण इलाकों की कीमत पर भी प्राप्त किया जा रहा है।

मुख्यशब्दः- ग्रामीण भारत , शहरी विकास , शहरी प्रणाली , आधुनिक वाणिज्यिक क्षेत्र , ग्रामीण और शहरीअर्थव्यवस्थाएँ

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

प्रस्तावना

ग्रामीण और शहरी भारत के बीच बदलते संबंधों के बारे में एक अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री पुरुषोत्तमन द्वारा बताया गया है। पुरुषोत्तमन और दो सहयोगियों सौरभ बंदोपाध्याय और अनिंद्य रॉय ने एक पत्र लिखा है, जिसका शीर्षक है, ष्क्या शहरी विकास ग्रामीण भारत के लिए अच्छा है ? जो इन सवालों को संबोधित करता है। शोध में , उन्होंने ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चार संबंधों को उजागर कियारू उत्पादन संबंध, उपभोग संबंध, वित्तीय संबंध और प्रवास। देश के उपभोग और उत्पादन के स्वरूप में तेजी से बदलाव के लिए शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एकीकरण की अधिक बारीक समझ की आवश्यकता है, न कि ग्रामीण-शहरी विभाजन के बारे में पारंपरिक मिथकों पर ध्यान देने की। पहला यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी भारत में तेजी से आर्थिक विकास तेजी से शहरीकरण को बड़ा रहा है ; दूसरा, ग्रामीण भारत अभी भी एक कृषि अर्थव्यवस्था है ; और तीसरा, कि ग्रामीण-शहरी असमानता बढ़ रही है। पिछले दो दशकों के दौरान, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले एक दशक के दौरान , शहरी अर्थव्यवस्था में 5.4% की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था औसतन 7.3% बढ़ी है। नवीनतम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने 2000 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 49% हिस्सा दिया। यह 1981-82 में 41% और 1993-94 में 46% की महत्वपूर्ण वृद्धि है।

जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 1981 में ग्रामीण-शहरी प्रवासन कुल ग्रामीण आबादी का हिस्सा 6.5% था, जबकि 2001 में यह गिरकर 2.8% हो गया। अध्ययन बताता है कि ष्शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक वृद्धि की घटती दर के साथ-साथ ग्रामीण-शहरी प्रवास की धीमी दरष् यह संकेत देती है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया वास्तव में आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप धीमी हो रही है। श्रम-गहन उद्योगों के विकास और शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश की कमी को रोकने वाली नीतियों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। वहीं ग्रामीण-शहरी असमानता के मुद्दे पर , अध्ययन इंगित करता है कि शहरी-ग्रामीण आय अंतर (या ग्रामीण आय में औसत शहरी अनुपात) 1990 के दशक के बाद से कम हो गया है। "हालांकि यह परिवर्तन बहुत आकस्मिक नहीं है, यह अन्य अर्थव्यवस्थाओं में हम जो देखते हैं उससे बहुत अलग तरीके से हो रहा है। उदाहरण के लिए , चीन में, ग्रामीण और शहरी असमानता वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ रही है।" साथ ही ग्रामीण रोजगार के आंकड़े भी दिलचस्प अंतर्दृष्टि को प्रकट करते हैं। 2000 और 2005 के बीच, ग्रामीण कृषि रोजगार वृद्धि 1% के रूप में कम थी। यह इंगित करता है कि कृषि क्षेत्र में ग्रामीण

इलाकों में नौकरियों में वास्तव में उल्लेखनीय वृद्धि को नहीं देखा गया है। इसके विपरीत , इसी अवधि के दौरान, गैर-कृषि नौकरियों में 20% की वृद्धि हुई है।

विश्व भर में, विकास और रोजगार के सबसे बड़े संचालकों में से एक खुदरा है। भारत में , दुर्भाग्य से, खुदरा क्रांति काफी देर से आई है। लेकिन यह माना जाता है कि शहरी खुदरा बिक्री ग्रामीण विकास को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देगी, कृषि और गैर कृषि दोनों के विकास में। भारत के खुदरा क्षेत्र का बाजार-आकार कुछ300 बिलियन डॉलर है, जिसमें से बमुश्किल 2% से 4% संगठित क्षेत्र में है। उद्योग, हालांकि, बड़े पैमाने पर परिवर्तन से गुजर रहा है और 2010 तक संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 20% से 25% तक बढ़ने की संभावना है। चूंकि ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखलाएं संगठित शहरी खुदरा विक्रेताओं के साथ एकीकृत हैं , इसलिए यह ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण संचालक होगा।

शहरीकरण (urbanization) वह प्रक्रिया है जिसमें लोग पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं और अक्सर आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।

औद्योगिक क्रांति ने नौकरी के अवसर पैदा करके शहरीकरण को जन्म दिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक और सामाजिक सुधारों के साथ शहरी क्षेत्रों में मैन पावर की मांग बढ़ी है।

शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मानव जाति के आवागमन से है और समाज परिवर्तनों को कैसे स्वीकार करता है। भारत वर्तमान में शहरी आबादी में वृद्धि की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। शहरीकरण के साथ सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में वृद्धि हुई है , लेकिन दूसरी ओर यह शहरी आबादी में अनियोजित विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है।

प्रवासन के कारण वृद्धि के साथ संयुक्त जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे आवास, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भारी बोझ डालती है। बेहतर रोजगार के अवसर , बेहतर शिक्षा , स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं , व्यावसायीकरण, बेहतर जीवन स्तर , सामाजिक स्थिति और इतने पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं।

आधुनिक समय की खेती में शहरीकरण के लिए जनशक्ति की आवश्यकता को कम करने वाली नई तकनीक शामिल है।शहरीकरण के कारण कई समस्याएं हैं , जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरीकरण के कारण भारत में कुछ मुख्य समस्याएं अति-जनसंख्या , गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट, बेरोजगारी, परिवहन, स्वच्छता, प्रदूषण आदि हैं।

शहर की सुविधाओं में विकास के लिए योजना और निवेश की आवश्यकता है। स्वच्छ शहरों और हरित शहरों का विकास आवश्यक है। आम जनता के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी, भोजन और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान होना चाहिए। परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को शिक्षित करना चाहिए।

भारत में शहरीकरण

शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों की वृद्धि शहरीकरण है। शहरीकरण का अर्थ समाज के परिवर्तन से भी है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। यह अत्यधिक

स्वीकार्य धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों ने बेहतर सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक विकास हासिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में इसके उन्नत आर्थिक और सामाजिक लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।निजी क्षेत्र के विकास में वृद्धि के कारण स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरीकरण शुरू हुआ। जनगणना २००१ के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 2001 में 28.53% थी, जो जनगणना 2011 में 31.16% थी। 2007 की एक रिपोर्ट में बताया गया की शहरों की जनसँख्या यदि ऐसे ही बढ़ती रही तो 2030 तक इसके 40.76% तक पहुँचने कोई उम्मीद है।

भारत में शहरीकरण के मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति , आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण , आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचा सुविधाएं , निजी क्षेत्रों का विकास , रोजगार के अवसर , भूमि के टुकड़े और जीवन स्तर बेहतर हैं।जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं , शहरीकरण के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शहरीकरण के सकारात्मक कारक रोजगार के अवसरों , बेहतर और उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं , आवास, परिवहन, नई तकनीक, सामाजिक एकीकरण, बिजली और जीवन स्तर के बेहतर मानक हैं।शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव बेरोजगारी , भीड़भाड़, ग्लोबल वार्मिंग, यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण , गरीबी, पानी की आपूर्ति में कमी , शहरी अपराध, कचरा निपटान के मुद्दे आदि है। गुजरते समय के साथ शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव बेहद बढ़ रहे हैं।

शहरीकरण की प्रक्रिया

टाउनशिप (बस्ती) की स्थापना की प्रक्रिया 7वीं शताब्दी के अंत से धीमी गति से शुरू हुई थी और केवल तराई-भाबर क्षेत्र में केंद्रित थी। 11वीं शताब्दी में कत्यूरी साम्राज्य के पतन के कारण , कुमाऊँ चंद शासन के अधीन आ गया और उन्होंने कुछ और शहरों की स्थापना की। कल्याण चंद (1560-1565) ने 1963 में राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया (पांडे , 1937: 258)। उसी समय अल्मोड़ा को नई राजधानी घोषित कर विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचा। रुद्र चंद ने अल्मोड़ा में कई किले , भवन और सड़कें बनवाईं। ऐसा अनुमान है कि चांद साम्राज्य के दौरान कुमाऊं में 50000 परिवार थे (पांडे , 1937:375)। गोरखाओं ने मोहन चंद (पाठक , 1988: 103) के आत्मसात होने के बाद 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। गोरखा सेना ने कुमाऊँ की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद से , पूरे कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमणों का एक लंबा दौर चला (पांडे , 1937: 383-385)। गोरखाओं की विनाशकारी गतिविधियों के कारण कई गांव वीरान हो गए थे। इसकी बसावट और कृषि बर्बाद हो गई , फलस्वरूप इसकी

जनसंख्या में कमी आई (एटकिन्सन, 1884: 621)। 1815 में, ब्रिटिश शासन ने गोरखाओं की जगह ले ली , इस प्रकार कुमाऊं में चंद शासन के बाद एक बार फिर राजनीतिक स्थिरता का दौर आया। ब्रिटिश कंपनी ने कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में अपने व्यापारिक केन्द्र खोले। एक व्यापारिक एजेंट रदरफोर्ड ने काशीपुर में एक कारखाना शुरू किया जहाँ भारी मात्रा में भांग उगाई जाती थी और कंपनी के निवेश के लिए अग्रिमों की एक प्रणाली तैयार की (एटकिंसन, 1884: 642)। 25 अप्रैल 1915 को अंग्रेजों ने गोरखा कब्जे से लाल-मंडी और नंदा देवी की प्रसिद्ध चौकी को खाली करने के बाद कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा को अपने अधीन कर लिया (एटकिंसन, 1884: 664)। शहरीकरण की प्रक्रिया एक बहुआयामी घटना है जो क्षेत्र की भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना से प्रभावित होती है। हिमालय में , मुख्य रूप से कुमाऊँ क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भौतिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण , शहरीकरण की प्रक्रिया देश के अधिकांश अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी रही है। यह संख्या और शहर के आकार दोनों में भिन्न है। उन्होंने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को बदलने और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुमाऊं हिमालय के शहरी केंद्रों के विकास में योगदान करने वाले मुख्य कारक ऊंचाई, इलाके, सूक्ष्म जलवायु विशेषताओं, पहुंच, तीर्थ और सुंदर परिदृश्य में अंतर हैं।

शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और शहरी क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ हद तक होने पर शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण के सकारात्मक प्रभावों में बेरोजगारों को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं, ढांचागत विकास और नई और उन्नत तकनीकों तक पहुंच शामिल है। शहरीकरण विकास की प्रक्रिया है। हालांकि , शहरों में शहरीकरण पर विशेष रूप से मेट्रो शहरों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शहरीकरण के सकारात्मक प्रभावों पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं:

- **दक्षता:** शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संसाधन प्रदान करने में अधिक कुशल हैं। साफ पानी, आवास और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से प्रदान की जाती हैं।

- **पहुंच:** बुनियादी संसाधनों के अलावा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं, उच्च और बेहतर शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन आदि की आसान पहुँच मिलती है।

- **बेहतर रोजगार:** बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अक्सर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। औद्योगीकरण और व्यावसायीकरण के कारण शहरों में कई नौकरी और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं।

- **शिक्षा:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक स्कूल , विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। छात्र अपने परिवारों के साथ या बिना उच्च शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। छात्र अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए शहरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कैरियर विकल्पों में से चुन सकते हैं।

- **स्वास्थ्य देखभाल:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कई स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- **बेहतर सामाजिक समामेलन:** शहरीकरण सांस्कृतिक और सामाजिक संलयन को बढ़ावा देता है। विभिन्न धर्मों, जातियों और लिंगों के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के मानदंडों को तोड़ते हुए एक साथ काम करते हैं।

शहरीकरण के मुख्य कारण:

शहरीकरण के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- औद्योगीकरण
- व्यावसायीकरण
- सामाजिक लाभ
- रोजगार के अवसर
- आधुनिकीकरण
- सरकार
- बेहतर शिक्षा

यहाँ इन कारकों पर एक नज़र है:

- **औद्योगीकरण**

औद्योगिकीकरण कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ने की अवधारणा है। औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करता है। विकासशील और विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति के साथ, अधिक से अधिक लोग बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं।

- **व्यावसायीकरण**

आधुनिक समय के व्यापार और वाणिज्य का भी शहरीकरण हुआ। आधुनिक समय में, विपणन संस्थानों के विकास और व्यापार के तरीकों ने शहरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर वाणिज्यिक अवसर और रिटर्न हैं। परिणामस्वरूप , लोगों को शहरी क्षेत्रों में लुभाया जाता है।

- **सामाजिक लाभ**

बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल , परिवहन, स्वच्छता और सामाजिक स्थिति जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कई सामाजिक लाभ हैं। खेल के मैदान , थिएटर, पार्क और क्लब जैसी बेहतर मनोरंजक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार , लोग आधुनिक जीवन शैली के लाभों का आनंद लेने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं।

- **रोजगार के अवसर**

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुख्य रूप से अपने जीवन यापन के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा , स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, बैंकिंग, मीडिया, टेलीविजन और खेल में रोजगार के कई अवसर हैं।

कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता है। प्राकृतिक आपदाओं और सूखे के समय में , लोगों को रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है। आधुनिक कृषि तकनीक के साथ खेती के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता शहरीकरण की ओर कम हो रही है।

- **आधुनिकीकरण**

शहरी क्षेत्रों में नई तकनीक , अवसंरचनात्मक विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं , उदारीकरण और बेहतर जीवन स्तर की विशेषता है। यह पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करता है।

- **सरकार**

प्रशासन का प्रबंधन भी शहरीकरण के लिए जिम्मेदार है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के प्रबंधन या स्थानिक के संदर्भ में शहर की वृद्धि के साथ प्रताड़ना को बनाए नहीं रखा है।

- **बेहतर शिक्षा**

ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल और कॉलेज सभी शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इस प्रकार युवा लड़कियां और लड़के या तो अकेले या अपने परिवार के साथ शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए शिफ्ट होते हैं।

शहरीकरण के दुष्प्रभाव

नीचे दी गई समस्याएं शहरीकरण के कारण होने वाली समस्याएं हैं:

अतिप्रजन

प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों में अधिक आबादी का मतलब है। जिन शहरों में हर एक दिन आबादी बढ़ रही है वे भीड़भाड़ वाले हैं। भारत के सभी बड़े शहरों में वर्तमान स्थिति यही है। मुंबई , चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली भीड़भाड़ वाले शहरों के कुछ उदाहरण हैं।

आवास

जब आबादी बढ़ती है, तो आवास की मांग भी बढ़ जाती है। आवास सुविधाओं की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक वित्तीय संसाधनों, गरीबी और बेरोजगारी की कमी हैं।

बेरोजगारी

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में लोगों के प्रवास के कारण है। आर्थिक अवसरों में वृद्धि शहरी आबादी में वृद्धि के साथ तालमेल रखने में विफल है।

झुग्गी इलाके में वृद्धि

शहरी क्षेत्रों में अनियोजित वृद्धि मलिन बस्तियों के प्रसार को बढ़ा रही है। भारत में स्लम बस्तियों में वृद्धि एक हड़ताली विशेषता है। शहरीकरण, गरीबी और अतिवृष्टि ने मलिन बस्तियों के विकास को बढ़ा दिया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति की उच्च दर ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों की पहुंच से परे है।

ट्रांसपोर्ट

परिवहन के लिए वाहनों के बड़े उपयोग ने यातायात की भीड़ को बढ़ा दिया है जिससे आवागमन धीमा और मुश्किल हो गया है।

शहरी अपराध

शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। गरीबी के कारण चोरी , जेब भरना, धोखाधड़ी और हत्या जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है।

वायु प्रदुषण

शहरीकरण वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। उद्योग पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और वायु प्रदूषण पैदा करने वाले ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ते हैं। वाहनों के बड़े उपयोग से ईंधन के दहन से गैसें निकलती हैं। लैंडफिल से बड़ी मात्रा में कचरा जलाया जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है।

पानी

जीवन को बनाए रखने के लिए पानी प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शहरों में भीड़भाड़ के कारण पानी की आपूर्ति मांग की तुलना में कम हो रही है।

कचरा निपटान

शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की संख्या बढ़ने के साथ कचरा निपटान की समस्या बढ़ जाती है। शहरों में बड़ी मात्रा में कचरा स्वास्थ्य के गंभीर मुद्दों को बढ़ाता है। शहरों में अधिकांश क्षेत्रों में कचरा निपटान की सुविधा नहीं है। जब लैंडफिल को अपने आस-पास के वातावरण में पूरी तरह से जहरीला रिसाव हो जाता है , तो मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड आदि जैसी बीमारियों को आमंत्रित करते हुए, हवाई यात्रा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया फैलाती है।

निष्कर्ष

शहरीकरण एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले , शहरी परिदृश्य में रहने वाली आबादी में वृद्धि, दूसरी, शहरी बस्तियों की बढ़ती संख्या और तीसरे , मौजूदा शहरी निर्माण के विस्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। शहरों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण से शहरी प्रवासन , विशेष रूप से विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हुई , जिसकी भरपाई शहरी निर्माण के स्थानिक विकास से की जाती है। शहरी विस्तार इस प्रकार शहरी स्थान में वृद्धि की एक घटना है , जिसके परिणामस्वरूप शहरी भूमि का उपयोग निकटवर्ती ग्रामीण भूमि पर, शहरी सीमा पर आक्रमण में होता है। शहरी विस्तार की प्रक्रिया द्वारा शहरी सीमा पर शहरी आबादी का क्षैतिज फैलाव भूमि उपयोग और भूमि कवर में परिवर्तन लाता है। भूमि परिवर्तन, भूमि उपयोग और भूमि कवर का परिवर्तन शहरी अंतरिक्ष में एक अनिवार्य घटना है।

संदर्भग्रंथ सूची

- वाल्कनबर्ग (2020) द वर्ल्ड लैंड यूज सर्वे। आर्थिक भूगोल, 26, 1 - 5।
- बेरी (2021) बेसिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन. गिन्सबर्ग (एड) , एटलस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
- निकोलस (2018) आर्थिक विकास में एक कारक के रूप में एक कृषि अधिशेष। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जर्नल, 71 1-29।
- हाउसर (2018) अर्बनाइजेशन- एन ओवरव्यू, द स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन। पृष्ठ.156, जॉन विली संस, न्यूयॉर्क।
- नॉर्दर्न, आर.एम. (2019) अर्बन जियोग्राफी, पृष्ठ.152, जॉन विली संस इंक. न्यूयॉर्क।
- गिरि एच.एच. (2016) चेंजेज इन लैंड यूज पैटर्न इन पंजाब। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 14, नंबर 2, 73-90।
- शाहब एफ। (2020) शहरी विस्तार और कृषि भूमि का नुकसान - सहारनपुर शहर , भारत पर एक जीआईएस आधारित अध्ययन। पर्यावरण और शहरीकरण, 12, 133 - 149।
- मैसर, आई. (2021) हमारे शहरी भविष्य का प्रबंधन: रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली की भूमिका। हैबिटेट इंटरनेशनल, 25, 503-512।

- चांदना, आर.सी. (2021)। रीजनल प्लानिंग: ए कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट , कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पीपी 1-80।
- रामचंद्र, टी. वी., ऐथल, बी. एच., और सौम्यश्री, एम. वी. (2018)। अहमदाबाद शहर, भारत के कपड़ा केंद्र में शहरी गतिशीलता के स्थानिक पैटर्न की निगरानी। स्पैटियम इंटरनेशनल रिव्यू , 1(31), 85–91।
- अलघ, वाई. के. (2018) स्टेट ऑफ द इंडियन फार्मर: एन ओवरव्यू , एकेडमिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दिल्ली।
- दत्ता, आर. (2017) एस्टेट बजटीय संसाधन और राजस्थान का कृषि विकास। अनुसंधान अध्ययन, 35।
- देव, एम.एस. (2018) एम्प्लॉयमेंट: ट्रेंड्स , इश्यूज एंड पॉलिसीज , इन इनक्लूसिव ग्रोथ: एग्रीकल्चर , पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट (एड्स), पी.390, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- अग्रवाल बी. (2019) ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, पृ. 122-148, एबीडी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- दाधीच, पी.एन. (2021) एवोल्यूशन ऑफ अर्बन चेंज पैटर्न एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स केस ऑफ जयपुर। भूविज्ञान, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 43, 245-286।
- गुप्ता, के. (2021) अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ इन इंडिया , इन सेंसस एज सोशल डॉक्यूमेंट , पृष्ठ 184, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
- भाकरे, पी. (2020) महाराष्ट्र के पुणे डिवीजन की जनसंख्या संरचना में स्थान-अस्थायी परिवर्तन। पीएच.डी. थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, 221।